e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 1, January 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र: दशा और दिशा

डॉ. सुरेन्द्र सिंह

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सार

लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ तमाम मुश्किलें ही भारत को असाधारण लोकतंत्र बनाती हैं'

भारत में स्वतंत्रता के बाद 60 साल में राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र ख़ासा मज़बूत हुआ है, लेकिन गाँव-तहसील स्तर पर अलोकतांत्रिक व्यवहार और हिंसा भी नज़र आती है.

भारत एक बहुत ही असाधारण लोकतंत्र है जिसकी कुछ बहुत ही मज़बूत लोकतांत्रिक विशेषताएँ हैं और कुछ बहुत ही अलोकतांत्रिक विशेषताएँ भी हैं.

कुलमिलाकर देखा जाए तो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ तमाम तरह की मुश्किलें ही आज़ाद भारत को एक असाधारण लोकतंत्र बनाती हैं.

भारतीयों ने लोकतांत्रित व्यवस्था में रहना पसंद किया है.

परिचय

उपलब्धियों की बात करें तो यही लोकतांत्रित ढाँचा है जिसने 'सेफ़्टी वॉल्व' का काम किया है और कभी-कभी असल मुद्दे भी सलुझाए हैं. नहीं तो भारत जैसा बड़ा और इतनी असमानताओं वाला देश भला अविभाजित कैसे रह सकता था?

भारत में लोकतांत्रिक परंपरा दूर-दूर तक फैल रही है और उसकी जड़ें और गहरी हो रही हैं. देखा गया है कि चुनावों में संपन्न वर्ग के मुकाबले, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ज़्यादा बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं.

दूसरी ओर विकसित देशों में उपेक्षित वर्ग मतदान में ज़्यादा संख्या में भाग नहीं लेता क्योंकि उसे चुनाव में भाग लेने का कोई ख़ास मक़सद नज़र नहीं आता.[1,2,3]

अब सवाल उठता है कि क्या अपनी स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ गए वर्ग की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी आस्था है?

ये आस्था का सवाल कम है और असल बात ये है कि वे इस व्यवस्था को ज़रूरी मानते हैं लेकिन काफ़ी नहीं. उन्हें लगता है कि इससे उनकी मदद होती है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, फिर चाहे ये पर्याप्त न हो.

आज़ादी के बाद के 20-25 साल में मज़दूरों और किसानों के संघर्ष, यानी आर्थिक मुद्दो पर आंदोलन ज़रुर हुए थे. लेकिन इसके बाद सांस्कृतिक मुद्दों पर असंतोष, आर्थिक असंतोष से ज़्यादा देखा गया है.

विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिहाज़ से फ़र्क तो रहा है लेकिन जनांदोलन सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर रहे हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि आर्थिक असंतोष रहा ही नहीं, लेकिन अब आर्थिक मुद्दों पर लोगों को एकजुट करना ख़ासा मुश्किल हो गया है.

अहम पड़ाव

पिछड़ों को आरक्षण देकर उनके अधिकार दिलाने का प्रयास लोकतंत्र का एक अहम पड़ाव रहा

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

भारतीय लोकतंत्र की असफलताओं की बात करें तो पिछले 15 साल में- 1990 के दशक से लेकर अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ गई है.

यदि लोकतांत्रिक राजनीति के पाँच मुख्य पड़ावों की बात करें तो पहला, आपातकाल का लागू किया जाना और उतना ही महत्वपूर्ण, फिर उसका दोहराया न जाना था.

दूसरा था मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करना यानी पिछड़ों को और अधिकार दिलाने का प्रयास.

आज़ाद भारत के लोकतांत्रिक सफ़र का तीसरा मुख्य पड़ाव था बाबरी मस्जिद विध्वंस और चौथा था वर्ष 1998 के पोखरण धमाके जिनसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बहुत सदमा पहुँचता.

पाँचवाँ मुख्य पड़ाव है वर्ष 2002 में गुजरात में गोधरा की घटना और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की हत्याएँ, जिसके लिए ज़िम्मेदार अधिकतर लोगों को केवल क़ानूनी तौर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी सज़ा नहीं मिली.

ये सब मुख्य पड़ाव है और इनमें हिंसा का पहलू भी रहा है. शायद मंडल आयोग सिफ़ारिशों को छोड़कर बाक़ी घटनाएँ लोकतंत्र के लिए नकारात्मक हैं.

'आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग स्थिति सुधारने में चुनावी व्यवस्था को ज़रूरी मानते हैं'

ये सब घटनाएँ इस बात का भी संकेत हैं कि भारत के उच्च वर्ग का किरदार किस तरह बदल रहा है. भारतीय लोकतंत्र असल में ‘आप पर कौन शासन करेगा,’ इसकी प्रतिस्पर्धा है.

ये उस लिहाज़ से लोगों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया कम है. लेकिन राज्यों के स्तर पर लोगों के पास काफ़ी विकल्प हैं जो एक सकारात्मक बात है.

संसद में 28 अलग-अलग राजनीतिक दल हैं और पार्टियों की नीतियों में फ़र्क देंखे तो वह भी ख़ासा है. अमरीका या ब्रिटेन में तो लोगों के पास विकल्प सीमित हैं.

सक्रिय ताकतें

आज के भारतीय लोकतंत्र और भविष्य के भारत की रचना में कौन सी ताक़तों की मुख्य भूमिका है?

इस संदर्भ में सबसे पहली ताक़त है अनिश्चित और धीमी गति से लेकिन लगातार बढ़ रहा हिंदुत्व जिसका प्रभाव केवल चुनावों में ही नहीं, बल्कि समाजिक रिश्तों [4,5,6]पर भी दिख रहा है.

दूसरी बड़ी ताक़त है पिछड़े वर्ग का अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाना. तीसरी ताक़त है दलितों का अपने अधिकारों और सत्ता में भागीदारी के लिए सक्रिय होना.

चौथा प्रभाव है मुसलमानों का पारंपरिक नेतृत्व के साथ असंतुष्ट होना, महिलाओं के अधिकार और समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करने और रोज़गार दिलाने का प्रश्न. इसके साथ ही यह समुदाय इस अहम सवाल का सामना कर रहा है कि ‘हम (मुसलमान) कहाँ जा रहे हैं?’

अन्य मुख्य पहलू हैं भारतीय राजनीतिक का क्षेत्रीयकरण और भारत के तथाकथित मध्य वर्ग का आगे बढ़ना- तथाकथित इसलिए क्योंकि ये मध्य वर्ग देश का लगभग 15-20 प्रतिशत उच्च और प्रभावशाली वर्ग है.

इन प्रभावों का मिश्रण और एक-दूसरे पर हावी होना वह पेचीदा तस्वीर पैदा करता है जिससे वर्तमान और भविष्य के भारत की रचना होगी.

क्षेत्रीय राजनीतिक दल आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय दलों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया है

मज़बूत जड़ें क्यों

भारत में लोकतंत्र की जड़ें पड़ोसी देशों के मुक़ाबले में मज़बूत क्यों हैं?

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं. आज़ादी के बाद के 20-25 साल में राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा. कई मायने में कांग्रेस आज़ादी से पहले ही इस 'रोल' के लिए तैयार थी और प्रशासकीय भूमिका निभा रही थी.

ये चाहे सतही तौर पर उस समय की भारतीय राजनीति का अलोकतांत्रिक पहलू प्रतीत हो, लेकिन उस समय कांग्रेस में कई धड़े थे जो अलग-अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे.

जब कांग्रेस का प्रभुत्व ख़त्म हुआ तो पहले ये राज्यों में हुआ. वहाँ आपस में मुक़ाबला करती काफ़ी हद तक स्थिर, दो-पार्टी या तीन-पार्टियों की व्यवस्था कायम हुई. इसके बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर कई पार्टियाँ सामने आईं.

राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने भारत की एकता को बल दिया- भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और राष्ट्रीय चुनावों को प्रांतीय चुनावों से अलग करना.

भाषा के आधार पर राज्यों के बनने से शायद उर्दू को छोड़कर बाक़ी सभी भाषाओं का विकास हुआ और राज्यों में लोगों की पहचान मज़बूत हुई.

अगर भाषा के आधार पर राज्य न बनते तो काफ़ी मुश्किलें हो सकती थीं.

इसके अलावा, राष्ट्रीय चुनावों को राज्यों के चुनावों से अलग कर दिए जाने से क्षेत्रीय पार्टियों को बल मिला और राज्यों के लोगों को अपने मुद्दे उठाना और उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना आसान हो गया। इससे आज़ाद भारत में लोकतंत्र मज़बूत हुआ।

विचार-विमर्श

एक तथ्य है कि मानव मस्तिष्क खुद ही अनुशासन में रहने के लिए नहीं बने हैं। हमें कोई बाहरी शक्ति अनुशासन में रहने के लिए विवश करती है और जहां निगरानी में कमी हो, छूट हो, वहां धीरे-धीरे उच्छृखंलता पसर जाती है। हाल ही में लिस्बन में राजनीतिक मनोवैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय सोसायटी के वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए नामचीन प्रोफेसर शॉन रोजेनबर्ग ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का हृस हो रहा है और लोकतंत्र इस दिशा में बढ़ रहा है कि वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। शॉन रोजेनबर्ग ने येल, आक्सफोर्ड तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है और उनकी विद्वता का सिक्का विश्व भर में चलता है। प्रोफेसर रोजेनबर्ग के इस निष्कर्ष को हम भावना का अतिरेक भी मान लें तो भी बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनकी उपेक्षा कर पाना संभव नहीं है।

शासन व्यवस्था तथाकथित अभिजात्य वर्ग के नियंत्रण से निकल कर सामान्य जनों के हाथ में आ गई है। बीसवीं सदी लोकतंत्र का स्वर्ण युग रही है। सन1945 में विश्व भर में कुल 12 देशों में लोकतंत्र था। बीसवीं सदी की समाप्ति के समय यह संख्या बढ़कर 87 तक जा पहुंची लेकिन उसके बाद लोकतंत्र का प्रसार रुक गया। कुछ देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा ने कब्जा कर लिया है या पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ब्राजील, अमरीका और भारत जैसे देशों में यह लगातार [7,8,9]शक्तिशाली हो रही है।

दक्षिणपंथी विचारधारा को जहां विश्व भर में सन 1998 में सिर्फ 4 प्रतिशत लोगों का समर्थन था, सन 2018 आते-आते यह बढ़कर 13 प्रतिशत तक जा पहुंचा है। लोकतंत्र को संभालना अत्यंत बुद्धिमता और मेहनत का काम है। सामान्य जन बुद्धिमता के उस स्तर तक पहुंचने में नाकाम रहा है जहां लोकतंत्र को समझा और संभाला जा सके।

तथाकथित उदारवादियों अव्यवस्था और भ्रष्टाचार से परेशान नागरिक अंततः दक्षिणपंथ की शरण में गए हैं और इस विचारधारा से सहमत हो गए कि शासन तो डंडे से ही चलता है। यानी, खुद हम नागरिक ही इस बात का समर्थन करते हैं कि कड़े अनुशासन और सजा के प्रावधान के बिना हम नैतिकता और कानून की परवाह नहीं करेंगे। यह सिर्फ आम जनता का विचार ही नहीं है बल्कि समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और उच्च शिक्षित लोगों की राय का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रोफेसर रोजेनबर्ग का कहना है कि अगले कुछ दशकों में पश्चिमी स्टाइल का लोकतंत्र नाकाम हो जाएगा, बहुत से देश लोकतांत्रिक व्यवस्था छोड़ देंगे और जो बाकी बचेंगे वे भी अपने आप में सिमटे के रहेंगे। समस्याएं जटिल हैं और दक्षिणपंथ उनके सरल समाधान प्रस्तुत करता है, यह अलग बात है कि उनमें से बहुत से या तो व्यावहारिक नहीं हैं। हम लोग दूसरों की असहमति बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, खुद से भिन्न विचारों से खुश नहीं होते और सूचना के समंदर में से सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते क्योंकि हम इसके लिए आवश्यक ज्ञान, विवेक, तर्क और अनुशासन की क्षमता का विकास नहीं कर पाए हैं।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

हमें इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे तेज़-तर्रार शासक कहीं ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि हम मानने लगते हैं कि शासन तो डंडे के जोर पर ही चलता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दशकों में धीरे-धीरे अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं का ढेर लग गया और बहुसंख्यक वर्ग ने स्वयं को उपेक्षित महससू करना शुरू कर दिया। तब अल्पसंख्यकों की धौंस थी, अब बहुसंख्यकों की तानाशाही है। हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि संतुलित व्यवहार के बिना यह तानाशाही और ज़ोर.जबरदस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकती। इससे सिर्फ समाज में वैमनस्य ही बढ़ेगा और खून के बदले खून या सिर के बदले सिर की संस्कृति आम हो जाएगी। लोकतंत्र की मांग है कि अनेकता वाले समाज में सद्भाव और उदारता के साथ ही चला जा सकता है। स्पष्ट है कि हमसे भिन्न तरह से सोचने और दिखने वाले लोगों का भी देश पर उतना ही हक है जितना कि हमारा, लेकिन दूसरी कौम के लोगो के साथ सामंजस्य बनाकर रखने के बजाय उनका मजाक उड़ाना और उन्हें नीचा दिखाना ज्यादा आसान काम है और आज हम वही कर रहे हैं। इसके लिए सच की आवश्यकता नहीं है, तर्क गढ़े जा सकते हैं। देशभक्ति और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा सकता है और उत्तेजित किया जा सकता है। ओवैसी हो या ठाकरे, सबने इस हथियार का प्रयोग बड़ी कुशलता और आसानी से किया है।

निष्ठाएं बदल गई हैं और आम भारतीय के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक संस्कृति और व्यवहार की उपेक्षा करना गर्व विषय बन गया है। रोजेनबर्ग की भविष्यवाणी कब सच्ची होगी, सच होगी भी या नहीं, यह कहना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि हम लोग एक खतरनाक रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिसके परिणाम शुभ होने के अवसर न के बराबर हैं। निकट भविष्य में जो काम और नीतियां हमें अपनी जीत जैसी प्रतीत होती हैं, वे ही बाद में हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं। अभी हम जिधर दौड़ रहे हैं यहां रास्ते में कोई स्पीड-ब्रेकर नहीं है और हमारे अंदर कोई ब्रेक नहीं है। यह अंधी दौड़ हमें कहां ले जाएगी, कहना मुश्किल है। समस्या यह नहीं है कि सबसे बड़ा नेता क्या सोचता है? समस्या यह है कि आम जनता क्या सोचती है?

आम जनता उग्र विचारों के समर्थन में कितना आगे तक जा सकती है। आज हम विदेशी घुसपैठियों की बात करें या अपने देश पर आक्रामण करने वाली जातियों के पूर्वजों की बात करें, हम यह भूल जाते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की भूल नहीं है, यह एक विचारधारा की भूल है। व्यक्ति को बदला जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है लेकिन विचारधारा में परिवर्तन उतना आसान नहीं है और एक बार जब हम किस विशिष्ट विचारधारा के समर्थन में उतर आए तो फिर हमारे लिए खुद को बदल पाना भी कई बार संभव नहीं हो पाता। प्रोफेसर रोजेनबर्ग इसी डर का इजहार करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र की सीमाएं छोटी होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं और यह बहुत संभव है कि आने वाले कुछ दशकों में लोकतंत्र से चलने वाले देशों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि उन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकेगा।

परिणाम

- भारत में लोकतंत्र का एक लंबा और गहन इतिहास रहा है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत भारतीय उपमहाद्वीप के लिये नए नहीं हैं।
    - शासक और शासित के बीच का संबंध पिता और संतान के समान माना गया है।
- भारतीय लोकतंत्र में धर्म (कर्त्तव्य) की अवधारणा महत्त्वपूर्ण है, जिसमें राजा (राज धर्म) और प्रजा (प्रजा धर्म) दोनों के दायित्व शामिल हैं।

- बुनियादी मूल्य
    - भारतीय लोकतंत्र के मूल मूल्य जैसे- समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन को रेखांकित करते हैं;
    - समावेशी निर्णय-प्रक्रिया के साथ लोकतांत्रिक पारिवारिक संरचनाओं का पारिवारिक महत्त्व देखा जाता है; सभाओं में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समावेशिता को दर्शाती है।
    - भारत की लोकतांत्रिक नींव, जो इतिहास और सामाजिक मूल्यों[10,11,12] में निहित है, धर्म द्वारा निर्देशित स्थायी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर ज़ोर देती है, यह शासकों तथा शासितों दोनों की भूमिकाओं को आकार देती है;
    - सहभागी लोकतंत्र की ऐतिहासिक परंपरा शासकों के चयन और अनुमोदन में जनता की भागीदारी को रेखांकित करती है, शासक की संभावना तथा सार्वजनिक सहमति के महत्त्व को उजागर करती है, व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने वाले के रूप में एक देखभाल करने वाले पिता को प्रतिबिंबित करती है।
- लोकतंत्र का दार्शनिक आधार
    - लोकतांत्रिक-आध्यात्मिक-सामाजिक लोकाचार: प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ, ऋग्वेद में कहा गया है: एकम् सद विप्रा बहुधा वदन्ति- "सर्वोच्च वास्तविकता एक है, ऋषि उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं।"

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

- "समानता लोकतंत्र की आत्मा है। भारत के दार्शनिकों, संतों और कवियों ने इसे पहचाना तथा सदियों से इसके महत्त्व का प्रचार किया।

प्राचीन काल से लोकतांत्रिक संस्थाएँ किस प्रकार विकसित हुई हैं?

- वैदिक युग में सार्वजनिक भागीदारी (6000 ईसा पूर्व - 1100 ईसा पूर्व)
  - चार वेद (ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद) राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक सिद्धांतों सहित एक व्यापक सभ्यतागत मूल्य प्रणाली को समाहित करते हैं।
  - विश्व की सबसे पुरानी रचना ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा, समिति तथा संसद जैसे प्रतिनिधि निकायों का उल्लेख है, ये शब्द आज भी उपयोग में हैं।
- महाकाव्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
  - रामायण व्यक्तियों के कल्याण के लिये शासन पर ज़ोर देती है, जैसा कि राम के सर्वसम्मति से अयोध्या के राजा के रूप में चयन में देखा गया था।
  - महाभारत में धर्म, आचार, नैतिकता और शासन पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर को भीष्म की सलाह, भगवद् गीता में कर्त्तव्यों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।
- महाजनपद और गणतंत्र (7वीं तथा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व)
  - व्यक्तियों का सामूहिक शासन, प्राचीन भारतीय प्रणालियों में एक प्रमुख विशेषता, महाजनपद शासन मॉडल में प्रकट हुआ: एक परिषद के साथ 15 राजत्व और 10 गणराज्य जहाँ प्रमुख चुना जाता था।
  - अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ 'लोकतांत्रिक' संस्थाओं- गण, पूग, निगम, जनपद पर प्रकाश डालते हैं।
- जैन धर्म
  - 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला आ रहा जैन धर्म, अनेकांतवाद के माध्यम से बहुलवाद को बढ़ावा देता है, यह स्वीकार करते हुए कि सत्य के कई पहलू होते हैं। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप सह-अस्तित्व और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है।
  - मूल सिद्धांत के रूप में अहिंसा के साथ जैन धर्म शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन करता है, जिसका आज भी भारत में पालन किया जाता है।
- बौद्ध धर्म (500 ईसा पूर्व से)
  - 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध संघ, प्रारंभिक लोकतांत्रिक प्रथाओं का उदाहरण था। इस भिक्षु समुदाय ने बौद्ध सिद्धांतों और लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार रखा, नेताओं के लिये खुली चर्चा तथा चुनाव को बढ़ावा दिया। बौद्ध सिद्धांत भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को आकार देते रहे हैं।
- जन नेता
  - प्रारंभिक भारत ने अराजकता की स्थिति में एक महासम्मत्त (महान निर्वाचित) का चुनाव करते हुए सहभागी शासन को अपनाया। एक बड़े हॉल में व्यक्तियों द्वारा चुना गया राजा, गणराज्य या व्यक्तियों के राज्य में उनकी सुरक्षा हेतु 'वासेट्ठ' (प्रमुख) के रूप में शासन करता था।
  - बौद्ध धर्म के लोकतांत्रिक सिद्धांतों ने शासकों को प्रभावित किया, जिससे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना सुनिश्चित हुआ। शिलालेखों में समृद्धि और गिरावट की रोकथाम के लिये नियमित चुनाव का आग्रह किया गया।
- कौटिल्य और अर्थशास्त्र (350 - 275 ईसा पूर्व)
  - लोकतंत्र नागरिकों को प्राथमिकता देता है, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौटिल्य द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के शासन ग्रंथ अर्थशास्त्र में ज़ोर दिया गया है।
  - यह दावा करता है कि शासक की खुशी और कल्याण व्यक्तियों की भलाई पर निर्भर करता है, जो भारत के सेवा करने के स्थायी लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतीक है, न कि शासन करने का।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

- मेगस्थनीज़ और डायोडोरस सिकुलस के रिकॉर्ड (300 ईसा पूर्व)
  - प्राचीन यूनानियों ने विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया। भारतीयों की एक सराहनीय प्रथा थी: किसी को भी गुलाम नहीं बनाना, समान स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। वैश्विक गुलामी 150 वर्ष पहले समाप्त हो गई, सच्चा लोकतंत्र इसे बाहर रखता है। लेकिन भारत ने कभी गुलामी नहीं अपनाई थी।
- अशोक का शासन काल (265 - 238 ईसा पूर्व)
  - एक राज्य लोकतंत्र का प्रतीक है जब कानून द्वारा संरक्षित समान अधिकार और सम्मान, व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं।
  - सम्राट अशोक ने कलिंग की जीत के बाद ऐसे शासन की स्थापना की, जो प्रत्येक पाँच वर्ष में व्यवस्थित मंत्रिस्तरीय चुनावों के माध्यम से शांति और कल्याण को बढ़ावा देता था। उनके आदर्श लोकतंत्र के प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित हैं।
- फाह्यान के अभिलेख (5वीं शताब्दी ई.पू.)
  - लोकतंत्र अधिकारियों को लोगों की सेवा करने का अधिकार देता है, फाह्यान ने लोगों, कानून के शासन और सार्वजनिक कल्याण के प्रति भारतीय सम्मान का पालन किया।
- खलीमपुर ताम्रपत्र (9वीं शताब्दी ई.)
  - गोपाल को लोगों ने एक अयोग्य शासक को प्रतिस्थापित करने के लिये चुना था। खलीमपुर ताम्रपत्र अव्यवस्था के अंत और न्याय के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं।
- श्रेणिसंघा प्रणाली (876 ई.)
  - भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन में गिल्ड और शहर के नेताओं सहित जवाबदेह प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव करना तथा उन्हें रखना शामिल है।
- उथिरामेरुर शिलालेख (919 ई.)
  - दक्षिण भारत के उथिरामेरुर मंदिर में शासक परांतक चोल प्रथम के शिलालेख एक हज़ार साल पहले के लोकतांत्रिक चुनावों और स्थानीय स्वशासन की पुष्टि करते हैं।
- विजय नगर साम्राज्य का शासन
  - सर्व-सम्मति' लोकतांत्रिक आधार है, जिसका उदाहरण दक्षिण भारत में विजयनगर है, जहाँ कृष्णदेव राय के सहभागी शासन, मंडलम, नाडु और स्थल में विभाजन, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन पर ज़ोर दिया गया था, जो लोगों के लाभ के लिये एक आदर्श राज्य था।
- पदीशाह अकबर (1556 – 1605 ई.)
  - पदीशाह अकबर (1556 - 1605 ई.) ने धार्मिक भेदभाव से निपटने के लिये "सुलह-ए-कुल" की शुरुआत करते हुए समावेशी शासन का अभ्यास किया।
  - उन्होंने समधर्मी धर्म "दीन-ए-इलाही" और 'इबादत खाना' के साथ सद्भाव को बढ़ावा दिया। नवरत्न परामर्शदाताओं ने अकबर के उन्नत लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रदर्शित करते हुए जन-समर्थक पहलों में सहायता की।
- छत्रपति शिवाजी (1630-1680 ई.)
  - मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी (1630-1680 ई.) ने लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया। उनके आज्ञा पत्र में अष्ट-प्रधान के लिये कर्त्तव्यों की रूपरेखा दी गई, समान अधिकार सुनिश्चित किये गए। शिवाजी की लोकतंत्र विरासत उनके उत्तराधिकारियों के माध्यम से कायम रही।
- भारत का संविधान (1947 से आगे)
  - डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली विविध संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान एक आधुनिक, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है।
  - यह समानता और सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करते हुए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों तथा संबंधों को रेखांकित करता है।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

  - संविधान कई संशोधनों के साथ लोगों के साथ तालमेल बिठाने के लिये विकसित हुआ है, जिसमें संघ, राज्यों और स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली का समावेशन शामिल है।
- आधुनिक भारत में चुनाव (1952 से आगे)
  - भारत, वैश्विक लोकतंत्र का एक स्तंभ, आज़ादी के बाद से 17 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और दस लाख से अधिक स्थानीय स्व-सरकारी चुनावों का अनुभव कर चुका है।
  - निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है, जो सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है तथा शासन के सभी स्तरों पर भारत के गहरे लोकतांत्रिक लोकाचार को दर्शाता है।

वे कौन से स्रोत हैं जो भारतीय लोकतंत्र को फिर से खोजने में मदद करते हैं?

- समृद्ध साहित्यिक विरासत: भारत के महाकाव्य महाभारत और रामायण, ज्ञान के स्थायी स्रोतों के रूप में कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र और धर्म की अवधारणाओं को बहुत प्रभावित करते हैं।[12,13,14]
- लोकतांत्रिक मूल्य: भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत पूरे इतिहास में चुनौतीपूर्ण समय में भी कायम रहे हैं। पश्चिमी और पारंपरिक दोनों मूल्यों के प्रभाव ने आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में योगदान दिया है।
- मूल्यों की निरंतरता: ऐतिहासिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी लोकतांत्रिक भावना को बरकरार रखा है और यह भावना संविधान एवं शासन प्रथाओं सहित इसकी लोकतांत्रिक संरचनाओं में परिलक्षित होती है।

लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- मूल्यों का पोषण:
  - भारत अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से मौलिक मूल्यों का पोषण करते हुए "लोकतंत्र की जननी" के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से प्रभावित देश का समृद्ध इतिहास लोकतांत्रिक सिद्धांतों तथा स्थायी नैतिक मूल्यों के संवर्द्धन में योगदान देता है।
- जन जागरूकता:
  - भारत जन जागरूकता को बढ़ावा देकर "लोकतंत्र की जननी" के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के साथ राष्ट्र अपने नागरिकों के बीच जुड़ाव, राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिये एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
- आधुनिक शिक्षा:
  - भारत, आधुनिक शिक्षा में लोकतंत्र की जननी के रूप में एक मज़बूत लोकतांत्रिक नींव के साथ पीढ़ियों को आकार देते हुए महत्त्वपूर्ण विचार, समावेशिता और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले पाठ्यक्रम के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।
- G20 जैसे मंचों पर वैश्विक नेतृत्व
  - भारत की प्रतिबद्धता आर्थिक स्थिरता और सतत् विकास के G20 लक्ष्यों के अनुरूप है। कुछ वैश्विक अभिकर्त्ताओं के विपरीत भारत का लोकतांत्रिक लोकाचार खुला संवाद, मानवाधिकार और समावेशी नीतियों का समर्थन करता है।
  - भारत विकासशील देशों की आवाज़ को बुलंद करता है, निर्णय लेने में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और विविध दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के वैश्विक महत्त्व को रेखांकित करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ के लिये चर्चाओं एवं नीतियों को आकार देता है।
- भारत का नेतृत्व
  - भारत की G20 की अध्यक्षता लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देश का लक्ष्य उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना और वैश्विक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है।
- सामूहिक शक्ति
  - भारत की प्रगति और दृष्टिकोण इसके लोगों की सामूहिक शक्ति पर आधारित है। चुनौतियों पर काबू पाने और राष्ट्रीय एवं वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सहयोग, सर्वसम्मति और एकता की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

नई दिल्ली में संसद 20 (Parliament-20) शिखर सम्मेलन ने विश्व के सामने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और मूल्यों को प्रदर्शित किया। समावेशिता, समानता तथा सद्भाव पर ज़ोर भारतीय लोकतंत्र का केंद्र है।

G20 में भारत की भूमिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने व अपने लोगों की सामूहिक ताकत में उसके विश्वास को दर्शाती है। देश शिक्षा तथा जन जागरूकता पहल के माध्यम से भावी पीढ़ियों को इन शाश्वत लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिये काम कर रहा है।

निष्कर्ष

देश में लोकसभा के चुनावों का दौर चल रहा है और कहा यह जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में चुनावों को एक उत्सव की भाँति लिया जाता है। भारत के लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा भी है और हमारा निर्वाचन आयोग कई विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों में होने वाले चुनावों के संचालन में सहयोग भी देता है।

लोकतंत्र सूचकांक (Democracy Index) में भारत की स्थिति

लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल दुनियाभर के देशों के लिये डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। 2018 के लिये 167 देशों का यह सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल की तुलना में भारत को एक पायदान का फायदा मिला है, लेकिन इसके बावजूद भारत को दोषपूर्ण लोकतांत्रिक (Flawed Democracy) देशों की श्रेणी में रखा गया है। जहाँ तक स्कोर का सवाल है, पिछले 11 सालों में भारत को 2017 और 2018 दोनों वर्षों में समान रूप से सबसे कम स्कोर मिला। इस रिपोर्ट में एशिया की स्थिति में सुधार की प्रशंसा की गई है। लेकिन, चिंता का विषय यह है कि एशिया के अधिकतर देशों को दोषपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में रखा गया है।

- द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यह दुनिया के बदलते हालात पर नज़र रखती है और दुनिया की आर्थिक-राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देश विशेष की सरकार को खतरों से आगाह करती है।

पाँच पैमानों पर दी जाती है रैंकिंग

इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैरामीटर्स पर किया गया है- चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Pluralism), सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। गौरतलब है कि ये सभी पैमाने एक-दूसरे से जुड़े हैं और इन पाँचों पैमानों के आधार पर ही किसी भी देश में मुक्त और स्वच्छ चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जाता है। इस रिपोर्ट में 9.87 अंकों के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर और 1.08 अंकों के साथ उत्तर कोरिया सबसे आखिरी स्थान पर है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में दुनिया के 167 देशों को शासन के आधार पर चार तरह के पैरामीटर्स पर रैंकिंग दी गई है, जिनमें पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड शासन और सत्तावादी शासन शामिल हैं।
- 167 देशों में केवल 20 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक देश बताया गया है और इसके तहत 167 देशों की केवल 4.5 फीसदी आबादी शामिल है।
- सबसे ज़्यादा 43.2 फीसदी आबादी दोषपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में बसती है और इसके तहत कुल 55 देश शामिल हैं।
- हाइब्रिड शासन के तहत 39 और सत्तावादी शासन के तहत 53 देशों को शामिल किया गया है।
- मध्य-अमेरिका का कोस्टा रिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी से निकलकर पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में जगह बना ली है।
- मध्य अमेरिका के ही निकारागुआ में लोकतंत्र पर भरोसा कम हुआ है और वह दोषपूर्ण लोकतंत्र से सत्तावादी शासन की श्रेणी में चला गया है।
- 2017 के मुकाबले 2018 में जहाँ 42 देशों के कुल स्कोर में कमी आई है, वहीं 48 देश ऐसे भी हैं जिनके कुल अंकों में बढ़ोतरी हुई है।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

लोकतंत्र के विभिन्न पैमानों पर भारत की स्थिति

इस रिपोर्ट में 167 देशों की सूची में भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया समूह में शामिल भारत को छठा स्थान मिला है। भारत को कुल 7.23 अंक मिले हैं। अलग-अलग पैमानों पर देखें तो चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में 9.17, सरकार की कार्यशैली में 6.79, राजनीतिक भागीदारी में 7.22, राजनीतिक संस्कृति में 5.63 और नागरिक आजादी में 7.35 अंक भारत को दिये गए हैं।[12,13]

- रिपोर्ट के मुताबिक पहचान की राजनीति भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है। यानी यहाँ किसी भी पार्टी के एक चेहरे के आधार पर वोट डालने का चलन प्रभावी रूप से है। यही कारण है कि एक सामान्य उम्मीदवार जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, उसे अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिये बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
- रिपोर्ट में भारत की मुक्त और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा भी की गई है। यही वज़ह है कि चुनाव प्रक्रिया के मामले में भारत को 9.17 अंक मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ, सरकार की कार्यशैली को लेकर 6.79 अंक दिये गए हैं।
- रिपोर्ट में भारत सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराहट पर भी चिंता जताई गई है। साथ ही, किसानों, रोज़गार और संस्थागत सुधार के मामले में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया गया है। यही वज़ह है कि भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है।

कितना सफल है भारत का लोकतंत्र?

अपने 71 वर्षों के सफर में भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा, यह देखने के लिये इन वर्षों का इतिहास, देश की उपलब्धियाँ, देश का विकास, सामाजिक-आर्थिक दशा, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की ज़रूरत है। भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की कल्पना पर आधारित है। यहाँ की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। सिर्फ दक्षिण एशिया को ही लें तो, भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच यह अंतर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में उनके विशिष्ट धार्मिक समुदायों का दबदबा है। लेकिन, धर्मनिरपेक्षता भारत का एक बेहद सशक्त पक्ष रहा है। सूचकांक में भारत का पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में होने के पीछे यह एक बड़ा कारण है।

पिछले 71 सालों में देश ने प्रगति की है, काफी विकास किया है। देशवासियों का जीवन-स्तर पहले से बेहतर हुआ है। सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग एक ही समाज में एक साथ रहते हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने कामयाबी हासिल की है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया की छठी बड़ी शक्ति हैं। आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। लेकिन किसी लोकतंत्र की सफलता को आँकने के लिये ये पर्याप्त नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश का विकास तो हुआ है, लेकिन देखना यह होगा कि विकास किन वर्गों का हुआ। सामाजिक समरसता के धरातल पर विकास का यह दावा कितना सटीक बैठता है। दरअसल, किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने के क्या-क्या प्रयास हुए हैं।

इन सभी मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन कोई बहुत उल्लेखनीय तो नहीं ही रहा है।

क्या है वर्तमान स्थिति?

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की लगभग 36 करोड़ आबादी अभी भी स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता से वंचित है। दूसरी तरफ, देश का एक तबका ऐसा है जिसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
- विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्से पर सिर्फ 1 फीसदी लोगों का कब्ज़ा है और यह असमानता लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह Oxfam के मुताबिक, भारत के इस 1 फीसदी समूह ने देश के 73 फीसदी धन पर कब्ज़ा किया हुआ है।
- लैंगिक भेदभाव भी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 108वें पायदान पर है और UNDP द्वारा जारी लिंग असमानता सूचकांक-2017 में भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है।
- लोकतंत्र का चौथा खंभा माने जाने वाले मीडिया की आज़ादी भी सवालों के घेरे में है। दरअसल, पेरिस स्थित गैर-सरकारी संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स-2018 में भारत पहले की तुलना में दो स्थान नीचे उतरा है और इसे 138वाँ स्थान मिला।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301043 |

- इन 71 वर्षों में अन्य बातों के अलावा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और कट्टरवाद को भी प्रश्रय मिला। इसकी वज़ह से असहिष्णुता की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जातिवाद की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं।

निस्संदेह इस तरह की परिस्थितियाँ लोकतंत्र की कामयाबी की राह में बाधक बनती है।

बहुत कुछ करना बाकी है

- लोकतंत्र की कामयाबी के लिये ज़रूरी है कि सरकार अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे। विकास के तमाम दावों के बावजूद देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी आदि बेहद गंभीर समस्याएँ है। आज़ादी के 71 सालों बाद भी करोड़ों लोग दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन-पद्धति के अंग होते हैं, लेकिन इन तीनों में ही अव्यवस्था का बोलबाला है और ये बेहद दबाव में काम करती हैं।
- जनता की भागीदारी की कमी की वज़ह से ही हमारा लोकतंत्र महज एक 'चुनावी लोकतंत्र' बनकर रह गया है। चुनाव में मतदान का प्रयोग एक अधिकार के रूप में नहीं, एक कर्त्तव्य के रूप में किया जाने लगा है।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के लिये पहले बुनियादी समस्याओं को हल किया जाना ज़रूरी है ताकि लोकतांत्रिक[14] व्यवस्था को सफल बनाया जा सके।

संदर्भ

1. वी-डेम इंस्टीट्यूट (2023)। "वी-डेम डेटासेट" । 3 फरवरी 2023 को लिया गया ।
2. ^ दत्ता, अनीशा (22 जून 2023)। "भारत गुप्त रूप से वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक पर प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम करता है" । द गार्जियन ।
3. ^ पिल्लई, श्रेया और लिंडबर्ग, स्टाफ़न आई. (2021) "डेमोक्रेसी ब्रोकन डाउन: इंडिया" इन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021: ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल पीपी.20–21. वी-डेम इंस्टीट्यूट
4. ^ "भारत पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब तानाशाहों में से एक है," 2023 वी-डेम रिपोर्ट कहती है। द वायर । 7 मार्च 2023।
5. ^ "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतांत्रिक पतन" । वी-डेम संस्थान । 24 फरवरी 2020। मूल से 27 फरवरी 2021 को संग्रहीत । 3 जनवरी 2021 को लिया गया ।
6. ^ फोर्ब्स इंडिया इन्वेस्टिगेशन: भारत के सबसे अधिक गेरीमेंडर किए गए निर्वाचन क्षेत्र, कार्तिक शशिधर, 2019
7. ^ भारत ने 2022 के पुनर्निर्धारित चुनावी मानचित्र में कश्मीर क्षेत्र को 'गेरीमेंडर' किया
8. ↑ रॉबिन्सन, 1997, पृष्ठ 23
9. ^ डायोडोरस 2.39
10. ^ लार्सन, 1973, पृ. 45-46
11. ^ डे सैंटे, 2006, पृ. 321–3
12. ↑ आर., नागास्वामी (2003). उत्तरमेरुर . चेन्नई: तमिल कला अकादमी. पृ. 12–16.
13. ^ पद्मजा, टी. (7 मार्च 2023)। दक्षिण भारत में कृष्ण के मंदिर: तमिलनाडु में इतिहास, कला और परंपराएँ । अभिनव प्रकाशन। पृ. 88. आईएसबीएन 9788170173984.
14. ^ वैकुंठ पेरुमल मंदिर शिलालेख, उत्तिरामेरुर, टीएन और 1000 साल पहले लोकतांत्रिक चुनाव प्रथाएँ, नवरंग इंडिया, 02 सितंबर, 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

Scan to save the contact details